प्रकाशन का गौरवाशाली 14वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

वर्ष 14 | अंक 36 | मूल्य 15 रुपये | 26 जनवरी-01 फरवरी, 2025

दिव्य हिमगिरि परिवार की ओर से आप सभी को

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दिव्य हिमगिरि विज्ञान संप्रेषण VISIONGRAPHICS Media Solutions Himgiri

उत्तराखंड में इस बार गणतंत्र दिवस पर ‘लोकतंत्र उत्सव’ भी गूंजेगा

The TonsBridge School
The TonsBridge
DAY & RESIDENTIAL SCHOOL
CELEBRATING
75 YEARS
OF PROGRESS, UNITY, AND PRIDE
HAPPY REPUBLIC DAY
ACADEMIC BRILLIANCE AT
OUR CO-ED BOARDING SCHOOL
2025-26 REGISTRATIONS OPEN
Topped Uttarakhand
Class 12th CBSE Examination
(Ranked 2nd in India)
National School Awards
Most Technically Advanced School of Uttarakhand 2024
UTTARAKHAND EDUCATOR'S SUMMIT
Uttarakhand Educator Summit
Most Promising Senior Secondary School
CONSISTENTLY RANKED #1 CO-EDUCATIONAL SCHOOL
Discover the Joy of Learning at
The TonsBridge School
Our Co-Ed Boarding School offers an Exceptional Boarding Experience with Indian values-centered education, focusing on:
Harmony with Nature
Holistic Education
Cultural Integration
Mindfulness and Well-being
Technological Integration
Student- Centric Approach
Why Choose The TonsBridge School?
Comprehensive & Competitive Academic Curriculum
Global Perspective with Indian Value System
Holistic Growth Prioritizing Emotional Intelligence & Physical Well-being
Nurturing College-Ready Students
Comfortable Dormitories
Personlised Comfort
Well-Ventilated Spaces
Attached Washrooms
Study-Friendly Spaces
Nutritious Food
The School serves vegetarian meals with fresh cereals, vegetables and milk.
100% VEGETARIAN
Health & Wellness Priority
Recovery Lounge
Routine Treatments
General Ward
Isolation Ward
For More Info
Call: +91 9897292071
Visit Us at
www.thetonsbridge.com
Tons Confluence, Subharti Hospital Road,
Dehradun, Uttarakhand 248001

Rs.10,000/- Cash Award
on Every Final Selection
Sandeep Sir's
Estd. 2005
Doon Defence Academy®
An Ocean of Success
COUNTRY FIRST
20
साल बेमिसाल
MAKING THE
WARRIORS
सैनिक स्कूल के पैटर्न पर
NDA FOUNDATION COURSE
CLASS 8TH - 10TH (BOYS)
CLASS 11TH - 12TH (BOYS & GIRLS)
REGISTRATION Open
8266061666
Fully Residential Programme with Schooling (CBSE)
Scan and REGISTER NOW
Scan & Download Foundation Course PROSPECTUS 2025-26
ADMISSIONS Open for session 2025-26
NDA | CDSE | SSB | AFCAT | AGNIVEER
FOUNDATION
CLASS VIII - CLASS XII (CBSE BOARD)
MERCHANT NAVY
RIMC | RMS
SAINIK SCHOOL
Apply Now
MORE THAN 13500+ SELECTION IN LAST 20 YEARS
Address : हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है।
Opposite Green View Apartments
Sahastradhara Road, Near IT Park,
Dehradun - 248001 Uttarakhand
Contact :
+91 9897030757, +91 8279640145
+91 8266061666, +91 7895616868
www.doondefenceacademy.com

वर्ष 14 | अंक 36

दिव्य हिमगिरि

26 जनवरी-01 फरवरी, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार : डॉ. रजनीश गौतम
पौडी : रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार : के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर : हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली : मुकेश रावत
रुड़की : श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल : शीतल तिवारी
अल्मोड़ा : संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर : अजय शर्मा
प्रसार : रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

आठवां वेतन या रोजगार जरूरी

आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देने के केंद्र सरकार के फैसले ने स्वाभाविक ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह बात भी सही है कि आयोग के फैसले लागू होने से अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा, जो खासतौर पर पिछली दो तिमाहियों से कुछ संघर्ष करती दिख रही है। लेकिन इन बातों के साथ नौकरशाही और सरकारी अमले को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि देश में सरकारी तंत्र के जरिए जनकल्याण की स्कीमों को लागू कर आम लोगों के जीवन में क्वॉलिटी लाने वाले कर्मचारियों का वेतन भी संतोषजनक होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि महत्वाकांक्षी और योग्य युवाओं की दिलचस्पी इन सेवाओं में बनी रहनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी इस लिहाज से भी जरूरी होती है कि इससे अर्थव्यवस्था में मांग को मजबूती मिलती है। यह बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि भारतीय इकॉनमी में कंजम्पशन का योगदान 60 फीसदी के करीब है। इधर, अर्थव्यवस्था में मांग अपेक्षा के मुताबिक नहीं बढ़ रही है। ऐसे में आशा है कि जब आयोग के फैसले लागू होंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में डिमांड को मजबूती देने में मदद मिलेगी। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि अगर देश को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो बड़े सुधार टाले नहीं जा सकते। इनमें भूमि और श्रम सुधारों के साथ नौकरशाही पर बढ़ते खर्च पर लगाम लगाने की जरूरत को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहले ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के खर्च का बोझ इतना ज्यादा है कि सरकार के लिए खाली पदों को भरना एक चुनौती है। सरकारी सेवाओं का आकर्षक बने रहना जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति भी ठीक नहीं कि पढ़े-लिखे और योग्य युवा महज सरकारी नौकरी के इंतजार में अपने कीमती साल घर बैठे बर्बाद करने में समझदारी मानने लगें। एक तरफ जॉबलेस ग्रोथ और दूसरी तरफ सरकारी भर्तियों पर अघोषित रोक से हालात गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में खास तौर पर जरूरी हो जाता है कि फैसला करते समय जल्दबाजी न की जाए। सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार करते हुए संतुलित नजरिया अपनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

कुँवर राज अस्थाना

गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की शुरू हुई तैयारी

27 जनवरी को मुख्य सेवक सदन में यूसीसी कर नियमावली एवं पोर्टल का लोकापर्ण करेंगे मुख्यमंत्री

26 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अपने अस्तित्व में आ जाएगा। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने हेतु नियमावली एवं पोर्टल का लोकापर्ण करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी के लिए हमें जनादेश दिया है। हम वादा पूरा कर रहे हैं। किसी भी धर्म के लोगों टारगेट नहीं कर रहे है। यूसीसी लागू होने से तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसके लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा।

सब कुछ अगर ठीक-ठाक रहा तो इसी इस बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अपने अस्तित्व में आ जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी इसी महीने लागू करने की तैयारी कर रही है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) इसी महीने यानी जनवरी में ही लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी के लिए हमें जनादेश दिया है। हम वादा पूरा कर रहे हैं। किसी भी धर्म के लोगों टारगेट नहीं कर रहे है। यूसीसी लागू होने से तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसके लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव से पहले सत्ता में दोबारा आने पर जनता से यूसीसी लाने का वादा किया था, जिसकी शुरुआत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि हमने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हमने राज्य विधान सभा में विधेयक पारित कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने भी 12 मार्च, 2024 को उसे अपनी मंजूरी दे दी जिसके बाद वह अधिनियम बन गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है, जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह देश और प्रदेश को बांटने की राजनीति है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, 'यह कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है। यूसीसी में सभी के लिए एक समान व्यवस्था और एक समान कानून है।' यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, विवाह-शून्यता, इच्छापत्रीय एवं गैर इच्छापत्रीय उत्तराधिकार, सहवासी संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) से जुड़े विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। अधिकारियों ने यहां बताया कि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की हैं, जिससे जनता को असुविधा नहीं हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस मामले पर एक्सरसाइज की जा रही थी और हमने संकल्प लिया था कि राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना है जो इसे लागू करने जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने यूसीसी नियमावली को दी मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट ने 20 जनवरी को मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी है। यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को आधार से लिंक किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी ने कहा राज्य में सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है। इससे पूरे देश को फायदा होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके लागू होने की तारीख की घोषणा की जाएगी। यूसीसी लागू होने के बाद कई नियम बदल जाएंगे। लिव इन में रहने वालों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी। उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बना चुकी है। 6 मार्च 2010 के बाद की गई शादी के लिए अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद 60 दिन के अंदर पंजीकरण करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकरण के लोगों को मिलेगा फॉर्म। विवाह पंजीकरण के साथ तलाक की भी सूचना देनी होगी। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है और यह बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा।

उत्तराखंड में इस बार गणतंत्र दिवस पर 'लोकतंत्र उत्सव' भी गूंजेगा

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में पहली बार गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र नगर निकाय चुनाव नतीजों की भी गूंज सुनाई देगी। देश के किसी भी चुनाव में शायद यह पहली बार होगा कि किसी चुनाव में वोटों की गिनती गणतंत्र दिवस के दिन भी जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि बैलट पेपर से हुए मतदान के पूरे नतीजे आने में दो दिन लग जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती शनिवार 25 जनवरी से सुबह शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बैलट पेपर से मतदान हुआ था इसलिए पूरा चुनाव परिणाम आने में दो दिन का समय लगेगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव की तारीखों का एलान करते समय राज्य निर्वाचन आयोग टाइमिंग का सही आंकलन नहीं कर सका। आयोग द्वारा हुई चूक धामी सरकार, पूरी पुलिस-प्रशासन लॉबी के साथ सुरक्षाकर्मियों और हजारों मतदान कर्मियों को भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री धामी को निकाय चुनाव के नतीजों के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह और इसी महीने 28 जनवरी को उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में देहरादून के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।

दिन सोमवार, तारीख 23 दिसंबर साल 2024 को उत्तराखंड निकाय चुनाव की तारीखों का एलान करते समय राज्य निर्वाचन आयोग टाइमिंग का सही आंकलन नहीं कर सका। राज्य आयोग ने उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव कराने और 25 जनवरी को वोटों की गिनती की तिथि घोषित की थी। लेकिन चुनाव आयोग को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने थे। बैलट पेपर से कराए गए चुनाव नतीजा आने में लंबा वक्त लगता है। चुनाव आयोग द्वारा हुई चूक धामी सरकार, पूरी पुलिस-प्रशासन लॉबी के साथ सुरक्षाकर्मियों और हजारों मतदान कर्मियों को भारी पड़ रही है। हालांकि इस मामले में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है लेकिन कहीं न कहीं अंदरखाने में गणतंत्र दिवस (राष्ट्रीय पर्व) के दिन काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को मायूसी भी है।

'उत्तराखंड में पहली बार गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र निकाय चुनाव नतीजों की भी गूंज सुनाई देगी।' सरकारी कर्मचारी के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत ही व्यस्त शेडयूल हो गया है। मुख्यमंत्री धामी को निकाय चुनाव के नतीजों के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह और इसी महीने 28 जनवरी को उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों की ओपनिंग सेरिमनी में देहरादून के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यह सब निकाय चुनाव की वोटिंग और काउंटिंग की गलत टाइमिंग की वजह से हजारों लोगों का राष्ट्रीय पर्व का उत्साह फीका पड़ गया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले शनिवार, 25 जनवरी से पूरे प्रदेश भर में शुरू हुई। देश के किसी भी चुनाव में शायद यह पहली बार होगा कि किसी चुनाव में वोटों की गिनती गणतंत्र दिवस के दिन भी

जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि बैलट पेपर से हुए मतदान के पूरे नतीजे आने में दो दिन लग जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती शनिवार 25 जनवरी से सुबह शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बैलट पेपर से मतदान हुआ था इसीलिए पूरा चुनाव परिणाम आने में दो दिन का समय लगेगा। हालांकि शनिवार को भी देर रात तक कई चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव नतीजों की पूरी तस्वीर गणतंत्र दिवस के बाद साफ हो पाएगी। इन चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि कुछ सीटों पर कई अन्य दल और निर्दलीय भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका और 43 नगर पंचायतों में काउंटिंग जारी है। साथ ही निगमों में पार्षद के 540, नगर पालिकाओं में सभासद के 444 और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्य के 298 पदों पर चुनाव की मतगणना हो रही है। पहली बार विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तरह निकाय चुनावों के परिणाम भी घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कुल 54 मतगणना केंद्र बनाए हैं। मतगणना के लिए 6366 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। निकाय चुनावों में परिणाम केवल राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर जनता की राय जानने का भी जरिया होंगे। मुकाबला कई जगहों पर कांटे का है और छोटे अंतर से हार-जीत तय हो सकती है। उत्तराखंड में शनिवार दोपहर तक निकाय चुनाव की मतगणना के बीच पहले रुझान में निर्दलीय प्रत्याशी दोनों ही राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में निर्दलीयों ने भी कई सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सबसे आगे नजर आ रही है। हालांकि अभी यह आंकड़े रुझानों तक है। वास्तविक स्थिति रविवार शाम तक ही स्पष्ट हो सकेगी।

सभी जिलों में अलग-अलग जगहों पर मतगणाना हो रही है। हर केंद्र पर सुरक्षा बल तैनात हैं और मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निकाय चुनावों के नतीजे राज्य में सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक संदेश देंगे। यह न केवल जनता की मौजूदा सरकार के प्रति राय बताएंगे, बल्कि आगामी चुनावों के लिए भी दलों की रणनीति तय करेंगे। प्रदेश में सभी की नजरें इन नतीजों पर हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उत्तराखंड के निकाय चुनावों में किसके सिर जीत का ताज सजेगा। उत्तराखंड के मतदाताओं में आम चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी मतदान का रुझान कम नजर आया है। 2018 निकाय चुनाव के 69.79 से लगभग 4 प्रतिशत गिरावट के साथ इस बार मतदान 65.41 प्रतिशत रहा है। जिलेवार आंकड़े देखें तो केवल अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में ही मतदान बढ़ा है। पिछले छह सालों के दौरान राज्य में नगर निगमों की संख्या 11 हो

राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड तैयार, ओपनिंग सेरेमनी में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद

उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है। इस खेल के आयोजन को लेकर देवभूमि में जश्न का माहौल है। आठ जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन होगा। इन खेलों में देशभर से करीब 10 हजार से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी से शुरू हो रहे इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आठ जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन किया जाएगा। संकल्प से शिखर तक टैग लाइन और ग्रीन गेम्स थीम पर होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की 26 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। 26 जनवरी को ट्रायथलान के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। हालांकि खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 14 फरवरी तक होने वाले इस समारोह में देश के सभी राज्यों के करीब दस हजार राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 35 खेलों से जुड़ी 47 स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 24 जनवरी को एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) की एडवांस टीम कार्यक्रम स्थल रजत जयंती खेल परिसर देहरादून पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब 2 घंटे तक अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक संपन्न होने के बाद करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे। जहां पर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया जाने को लेकर ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को परखा। यहां राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब हमें इस ऐतिहासिक पल का इंतजार है। पूरे देश के लोग भी राष्ट्रीय खेलों का इंतजार कर रहे हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और चूंकि राज्य मेजबान है, इसलिए राज्य के लोग उत्साहित हैं, सभी का स्वागत करेंगे और यह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा। हमारी देवभूमि भी खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी। उत्तराखंड में इस बार गणतंत्र दिवस पर 'लोकतंत्र उत्सव' भी गूंजेगा

चुकी है। श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगमों में पहली बार चुनाव हुए हैं। इससे पहले वे नगर पालिकाएं थीं।

इस बार भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाने जा रहा

इस साल भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। देश के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे देश में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हुआ था लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ही वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के उद्देश से भी ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल-कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम और कई जगहों पर अवकाश दिया जाता है। हालांकि गणतंत्र दिवस एक छुट्टी नहीं बल्कि अपने देश और उस की महानता को याद करने का दिन है। संविधान ही है जो भारत के नागरिकों के एक सूत्र में बांधे रखता है इसलिए यह दिन हमारे लिए बेहद खास है। संविधान वह दस्तावेज है जो बताता है कि भारत सरकार कैसे काम करती है और इस देश नागरिकों के क्या अधिकार व कर्तव्य हैं। यह दिन भारत में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों/विभागों की झांकी दिखाई जाएगी। ये झांकियां 'स्वर्णिम भारत विरासत और विकास' की व्यापक थीम का हिस्सा होंगी और भारत की विविध शक्तियों और इसके निरंतर विकसित होते सांस्कृतिक समावेश को एक शानदार भविष्य की ओर अग्रसर करती हुई प्रदर्शित करेंगी। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया से 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड शामिल होंगे, जो कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में शामिल होंगे। इस वर्ष, परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो होंगे। उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा।

महापौर: उत्तराखंड में इनके सिर सजा ताज

देहरादून
सौरभ थपलियाल
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 1,76,447

अल्मोड़ा
अजय वर्मा
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 9,136

हल्द्वानी
गजराज बिष्ट
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 71,962

ऋषिकेश
शंभू पासवान
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 23,958

हरिद्वार
किरण जैसल
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 48,650

काशीपुर
दीपक बाली
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 42,236

कोटद्वार
शैलेंद्र रावत
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 38,173

श्रीनगर
आरती भंडारी
दल: निर्दल
प्राप्त मत: 7,959

रुड़की
अनीता देवी
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 20,908गग

रुद्रपुर
विकास शर्मा
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 54,069

पिथौरागढ़
कल्पना देवलाल
दल: भाजपा
प्राप्त मत: 9,466

प्रौद्योगिकी के इस दौर में मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ी: डॉ मनोज श्रीवास्तव

आज के समय में मीडिया समाज की धारणा बदलने में सशक्त भूमिका निभा रहा है। भूमंडलीकरण के समय अत्यधिक खुलापन आने से ज्ञान और सूचनाओं के आदान प्रदान से विकास की संभावनाएं खुली है। मनोज श्रीवास्तव, उप निदेशक सूचना ने आईएमएस युनिशन यूनिवर्सिटी देहरादून में पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में विचार व्यक्त किया। उन्होने कहा मीडिया में टेकनॉलाजी के बढते प्रयोग से जहा लोगों कि परम्परागत धारणाएं बदली है, वही पर मीडिया की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

कार्यशाला में कहा गया नैतिक मूल्यों का पतन, अपसंस्कृति का प्रसार के साथ धर्म और संस्कृति की व्याख्या लोग अपनी सुविधानुसार कर रहे है। ऑनलाइन गेमिंग की समस्याए एक नई चुनौती बनकर आई है, और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। इन सब में मीडिया की बड़ी भूमिका है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों की क्रिएटिविटी समाप्त होने के साथ मानवीय संवेदनाएं लुप्त होने लगी है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने हमारे नवजवानों की धारण ाा बदलने में विशेष कारक है। आज युवा वर्ग का अधिकांश समय स्क्रीन टाइम पर व्यतीत हो रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और योग में निहित है। इस दौरान प्रो-वाइस चान्सलर श्री संतोष कुमार, रजिस्ट्रार श्री प्रणव कुमार, समन्वयक नीरज खत्री, स्पनिल सिन्हा इत्यादि थे।

COMBINED MEDICAL INSTITUTE

Uttarakhand 1st Multi Super - Speciality Hospital

26 JANUARY

Happy

REPUBLIC DAY

SPECIALITIES

- Critical Care
- Trauma care and Emergency services
- Arthroplasty (Joint Replacement Surgery)
- Orthopedic Surgery
- Shoulder & Arthroscopy
- Cosmetic & Aesthetic Surgery
- Dental Cosmetic & Implantology
- ENT and Head & Neck
- Gastroenterology Surgery
- General Surgery
- Gynecology
- Neurosciences & Neurosurgery
- Nephrology
- Cardiology
- Ophthalmology
- Pediatrics
- Pulmonology & Chest
- Radiology & Imagin

FACILITIES

- Flexible OPD Timings
- Cashless indoor Admissions
- Endoscopy
- Dialysis
- Digital Xray
- Sonography
- CT Scan
- Pharmacy
- Cath Lab
- Corporate Empanelments
- Pathology Investigations
- Modular Operation Theaters
- Color Dropier
- E.E.G.

24 x 7 EMERGENCY

Contact: 8191805 805

54, Haridwar Road, Dehradun | Mobile- 0135-2520044, 2720411

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड

समस्त देशवासियों को

26 जनवरी

गणतंत्र दिवस

की

हार्दिक शुभकामनाएं

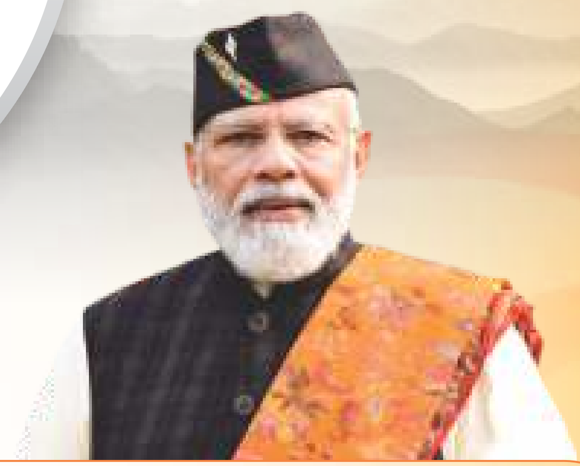

"माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक कहा है। हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।"

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

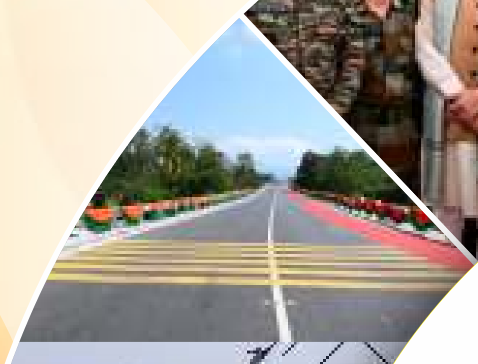

- नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रैंकिंग में उत्तराखण्ड देश में प्रथम स्थान पर
- पिछले तीन वर्षों में लगभग 19 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी
- पिछले 20 महीनों में जीएसडीपी में 13 गुना और पिछले 2 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 26% वृद्धि
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना

- एमएसएमई नीति: नए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन
- दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना: राज्य में 5000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन का सफल आयोजन
- बहुप्रतीक्षित बहुउद्देशीय जमरानी, सौंग और लखवाड़ बांध परियोजनाएं प्रगति पर
- रेल, रोड, रोपवे और एयर कनेक्टिविटी का विस्तार
- ऊधमसिंह नगर के खुरपिया फॉर्म में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्वीकृत
- हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
- उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: ₹3.56 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित, लगभग ₹85 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग गतिमान
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, सोलर प्लांट स्थापित करने पर 50% तक सब्सिडी
- नई फिल्म नीति: क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को कुल लागत का 50% या 2 करोड़ तक की सब्सिडी
- हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखण्ड महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध
- राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण
- लखपति दीदी योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण
- को-ऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
- मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना: राज्य के करीब पौने दो लाख गरीब परिवारों को साल में 3 मुफ्त रिफिल सिलेंडर
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण
- सख्त धर्मांतरण-विरोधी कानून: जबरन धर्मांतरण पर रोक
- समान नागरिक संहिता: सबका साथ सबका विकास

तेजस्विनी (मशाल)

संकल्प से शिखर तक

मौली (मैस्कट)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

CARMAN RES. & DAY SCHOOL

SHYAMPUR PREMNAGAR, DEHRADUN

Admission Open for the academic year 2025-2026

Affilated with the Council for the Indian School Certificate Examinations

Contact Us

01357964713/ 7088892438/
9891141891/ 7088999959/

Email: carmanschool87@gmail.com
Website: www.carmanschool.net

निकाय चुनावों में लापरवाही पर जारी हो रिपोर्ट

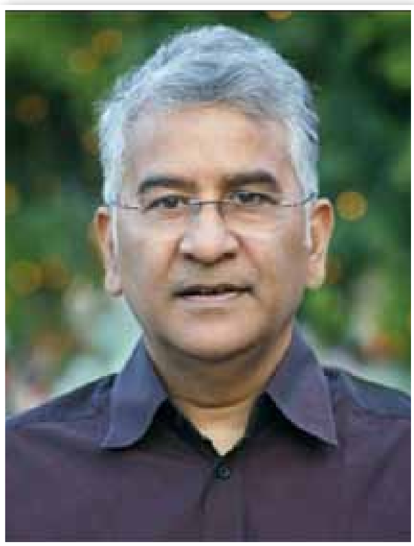

अनूप नौटियाल
सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने नगर निकाय चुनावों में हुई लापरवाही और अव्यवस्था की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट जारी करने और कमियों को चिन्हित कर भविष्य में इन्हें दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, उससे साफ दिखता है कि उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न करवाने में बेहद गैर जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया गया। कल के अव्यवस्थित निकाय चुनाव को देखते हुए उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के सामने तीन मांगें रखी हैं।

अनूप नौटियाल के अनुसार बहुत जगह जहां मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले, वहीं कई जगहों पर मतदान बहुत धीमी गति से हुआ। शाम 5 बजे मतदान का समय खत्म होने के बाद भी कई बूथों पर लंबी लाइनें थी। वोटर्स को अपना वोट डालने में जरूरत से ज्यादा समय लगा। यह तमाम लापरवाही किन कारणों से हुई, राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी विस्तृत जांच करनी जानी चाहिए और हर हाल में अगले दो हफ्ते में प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होनी चाहिए।

उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में लोगों के नाम न होने पर भी अफसोस जताया। कहा कि यह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं की संख्या सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। जनगणना न होने के कारण यह संख्या अरबन प्लानिंग में संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही मीडिया और शहरी मुद्दों पर काम करने वालों के लिए भी सहायक हो सकती थी। लेकिन, बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब होने के कारण यह आंकड़ा उपयोगी नहीं रह गया है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश के समस्त निकायों में कुल कितने लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे, इसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जांच की जाए और एक महीने के भीतर वार्डवार और निकायवार मिसिंग वोटर्स की सूची जारी की जाए।

अपनी तीसरी मांग रखते हुए अनूप नौटियाल कहा कि अगले एक महीने के दौरान राज्य के सभी 100 नगर निकायों में चुनावी स्टेकहोल्डर सभाओं का आयोजन किया जाए। इन सभाओं में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों, चुनाव में किसी न किसी रूप से सक्रिय रहे सामाजिक संगठनों के लोगों, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

इन चुनावी स्टेकहोल्डर सभाएं में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिनके कारण चुनाव में अव्यवस्था और लापरवाही हुई और उनसे सबक लेते हुए भविष्य में सुधार के लिए रोडमैप बनाना चाहिए। सभाओं में निकले निष्कर्ष के आधार पर भी विस्तृत रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले चुनावों में इन कमियों को दूर करते हुए चुनावी सुधार किए जा सकें।

पढ़ाई के साथ-साथ जीवन मे नैतिकता एवं राष्ट्र के प्रति देशभक्ति को भी प्राथमिकता देनी होगी: डॉ आशीष सेमवाल

24 जनवरी 2025 को माया देवी विश्वविद्यालय परिसर मे 75 फुट ऊचां झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेजर जरनल श्री गुलाब सिंह रावत एवीएसएम, वाई एस एम, एसएम (सेवानिवृत) एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जुयाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आशीष सेमवाल ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ विश्वविद्यालय की उपाध्यक्षा डॉ. तृप्ति जुयाल सेमवाल द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत से किया गया उसके बाद सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। 75 फीट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को मुख्य अतिथि मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से फहराया।

मुख्य अतिथि द्वारा वन्देमातरम एवं भारत माता की जय के नारों के साथ सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए वीरों की शहादत एवं स्वतंत्रता सेनानियो के बलिदान के बारे मे बताया।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आशीष सेमवाल ने सभी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ जीवन मे नैतिकता एवं राष्ट्र के प्रति देशभक्ति को भी प्राथमिकता देनी होगी।

कार्यक्रम मे वन्देमातरम संस्था से राजेश सेमवाल, गौरव जुयाल, डॉ. सीता जुयाल, अम्बिका जुयाल, उपकुलपति डॉ. मनीष पाण्डे आदि उपस्थित थे।

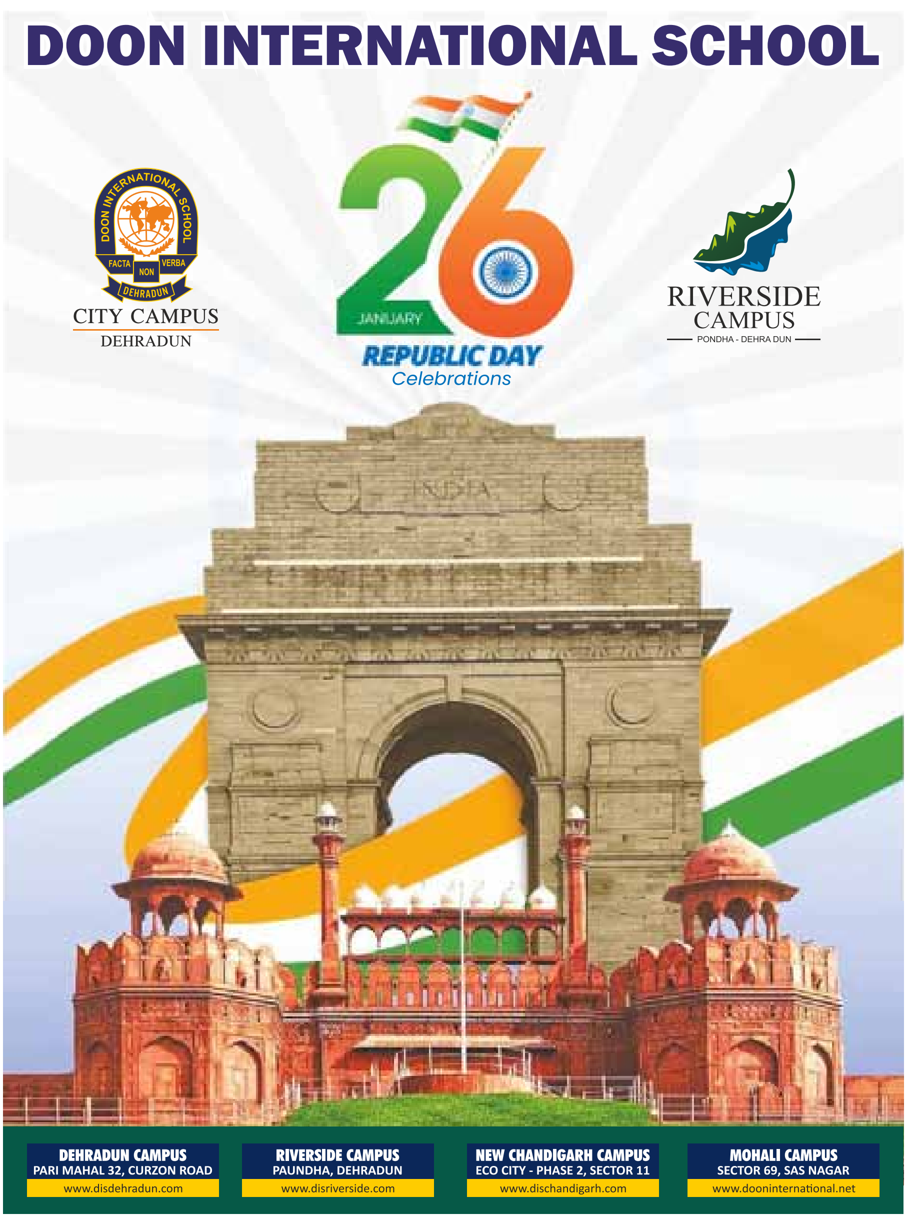

ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में उभरे डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम फैसले लिए। उन्होंने सबसे पहले बाइडन प्रशासन के 78 फैसले रद कर दिए। वहीं, यूएस-मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने एलान कर दिया कि मैक्सिको सीमा पर फिर से दीवार बनाई जाएगी और अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे, पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म करेंगे। मैं अपने देश पर विनाशकारी हमले को रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर सेना भेजूंगा। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता भी खत्म करने का एलान किया। फिलहाल कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताया और इस पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। वहीं अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है।

20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत दुनिया भर में सुर्खियों में है। राष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप लिए गए ताबड़तोड़ फैसलों के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की नींद उड़ गई है। भारतीय प्रवासियों में भी खलबली मची है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18 हजार भारतीयों की देश वापसी होने वाली है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे, पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म करेंगे। मैं अपने देश पर विनाशकारी हमले को रोकने के लिए दक्षिणी सीमा पर सेना भेजूंगा। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता भी खत्म करने का एलान किया। इसमें कोई संशय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कहीं अधिक ताकतवर राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। उनकी नई आर्थिक रणनीति में जहां समृद्ध अमेरिका के सपने को साकार करने के लिए आयात शुल्कों को बढ़ाना शामिल है। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम फैसले लिए। उन्होंने सबसे पहले बाइडन प्रशासन के 78 फैसले रद कर दिए। वहीं, यूएस-मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने एलान कर दिया कि मैक्सिको सीमा पर फिर से दीवार बनाई जाएगी। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है। जयशंकर ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का एच1बी और स्टूडेंट वीजा पर असर पड़े। डोनाल्ड ने कहा, एच1बी वीजा बंद नहीं होगा। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। अमेरिका एच1बी वीजा किसी खास पेशे (आईटी, हेल्थ, आर्किट्रेक्चर) से जुड़े लोगों के लिए जारी करता है। ये वीजा पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2.80 लाख एच1बी में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को अमेरिका में सैकड़ों अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें निर्वासित किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है और सैन्य विमान का उपयोग करके सैकड़ों को निर्वासित किया है। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह 'मेरा अमेरिका प्रथम' की धारणा को प्राथमिकता देते हुए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जगह अमेरिकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने के इरादे जताए हैं। ट्रंप ने सबसे पहले चीन, कनाडा, मेक्सिको सहित उन शीर्ष पांच-छह देशों पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का संकेत दिया है, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सर्वाधिक है। मृत्युदंड को बहाल करेंगे, जिसे बाइडन ने निलंबित कर दिया था। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के बाद हार गए लेकिन चार साल बाद फिर राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हराया है। ट्रंप का पहला कार्यकाल 2017 से 2021

तक रहा। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति रहे थे। उनका पहला कार्यकाल 1885-89 तक और दूसरा कार्यकाल 1893-97 तक था। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। न्यूयार्क की एक जूरी ने ट्रंप को एक पोर्न स्टार को दी गई गुप्त रकम को छिपाने के लिए हेराफेरी करने का दोषी पाया है।

अमेरिका में ट्रंप के नागरिकता कानून के फैसले पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही लिए गए फैसलों के बाद देश में उथल-पुथल का माहौल है। ट्रंप के नागरिकता कानून के फैसले के बाद अमेरिका में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 150 साल पुराने नागरिकता कानून में बदलाव किया है। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का निर्णय किया है। इस फैसले से कई प्रवासियों में बच्चों को 20 फरवरी से पहले जन्म देने को लेकर होड़ मच गई है। अमेरिका में रहने वाले दुनियाभर के कई प्रवासी जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, वे चाहते हैं कि 20 फरवरी से पहले ही बच्चों को जन्म दे दिया जाए। इसके लिए वे सी सेक्शन यानी सर्जरी का रास्ता अपना रहे हैं। यह विकल्प चुनने वाली महिलाएं मुख्य रूप से प्रेग्नेंसी के 8वें या 9वें महीने में होती हैं। इस संबंध में न्यूजर्सी के एक चिकित्सक ने बताया कि जिन महिलाओं की डिलिवरी मार्च में होना है, उनके फोन आ रहे हैं कि वे समय से पहले डिलिवरी कराना चाहती हैं। भारतीय-अमेरिकी सांसद ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता नियम में यह परिवर्तन ये सांसद असंवैधानिक बता रहे हैं। अमेरिकी सांसद प्रमिला जायसवाल ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इसे लागू करना कानून और संविधान में स्थापित मिसालों के साथ मजाक होगा। दरअसल, राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता का अधिकार खत्म करने का आदेश दिया था। इसे लागू करने के लिए 30 दिन (19 फरवरी तक) का समय दिया है। वहीं गुरुवार देर रात एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताया और इस पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। सिएटल कोर्ट ने 4 राज्यों (वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन) की अपील पर ये फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 5

फरवरी को होगी। 22 राज्यों ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ 2 फेडरल कोर्ट में मुकदमे दायर किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाली महिलाओं ने 2022 में 2.55 लाख बच्चों का जन्म दिया था। ट्रंप के फैसले से हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता पर संकट आ गया है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े फैसले में से एक अमेरिका में जन्मसिद्ध अधिकार कानून को खत्म करने वाले आदेश पर रोक लग गई है। चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों वाशिंगटन एरिजोना इलिनोइस और ओरेगन की याचिका पर विचार करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफेनॉर ने ट्रंप प्रशासन के आदेश को लागू करने के अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को असंवैधानिक बताया है। एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और नीति को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक अस्थायी स्टे आदेश जारी किया। सिएटल में स्थित रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश जॉन कफनौर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और तीन अन्य डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया, ताकि कानूनी चुनौती जारी रहने तक अगले 14 दिनों के लिए कार्यकारी आदेश को रोक दिया जा सके। कफनौर ने कहा, मैं चार दशकों से बेंच पर हूं। मुझे कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें प्रस्तुत प्रश्न इतना स्पष्ट हो। न्यायाधीश ने पूछा, जब कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे। उन्होंने कहा कि यह उनके दिमाग को भ्रमित करता है कि बार का एक सदस्य यह दावा करेगा कि आदेश संवैधानिक था। नए आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से एक का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक का अमेरिका की सेना में होना जरूरी है।

ट्रंप का कहना है कि यह आदेश 'बर्थ टूरिज्म' और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। नागरिकता हासिल करने के मकसद से प्रवासी अमेरिका जाकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे बच्चे को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। अमेरिका की संविधान में हुए 14 वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब, अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा खुद ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है। भले ही उसके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी रही हो। अमेरिका में सबको बराबरी का अधिकार देने के मकसद से यह संविधान संशोधन 1868 में लागू हुआ था। काफी समय से राजनीतिक दल अवैध प्रवासियों और घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। खासतौर पर ट्रंप इसके सख्त खिलाफ थे।

डीडीए के छात्र-छात्राओं ने की एनडीए-153 कोर्स के लिए रिपोर्टिंग

शुभकामनाएं देते हुए डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता ने की उज्जवल भविष्य की कामना

देहरादून। संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के दस छात्र-छात्राओं ने एनडीए-153 कोर्स के लिए जनवरी माह में रिपोर्टिंग की। जबकि दो छात्रों ने आर्मी टेक्निकल एंट्री 52 कोर्स के माध्यम से सेना का हिस्सा बनने जा रहें हैं। सभी डीडीए डायमंड्स को डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता व उपनिदेशक दिव्या गुप्ता शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एकेडमी की परम्परा के अनुसार डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता द्वारा रिटर्न एग्जाम क्लियर करने वाले डीडीए डायमंड्स को एक-एक हजार रूपये व फाइनल सलेक्शन होने पर दस-दस हजार रूपये नगद आशीर्वाद के रूप में दिए गए। साथ ही सीडीएस क्लियर करने वाले व अग्निवीर बने डीडीए डायमंड्स को भी दस-दस हजार रुपये नगद आशीर्वाद के रूप में दिए गए। छात्रों की सफलता पर ख़ुशी जाहिर करते हुए संदीप गुप्ता ने कहा कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि तीन साल बाद ट्रेनिंग होने के बाद वे सभी डीडीए डायमंड्स की पीओपी में शामिल हो कर ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इंडियन आर्म्ड फोर्स ज्वाइन कर देश सेवा करने का सपना देख रहे भारत के युवा भी डीडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए-153 कोर्स ज्वाइन करने वालों में डीडीए डायमंड्स स्पर्श कोठियाल (एयर-19), आरब भांती (एयर-28), महिमा पंवार (एयर-34), पद्मजात बेलुरा (एयर-44), प्रिया मिश्रा (एयर-75), आशुतोष शर्मा (एयर-128), रचित शर्मा (एयर-134), करण गौड़ (एयर-141), यूवराज सिंह (एयर-292) व रणवीर बिष्ट (एयर-300) हैं। वहीं आर्मी टेक्निकल एंट्री 52 कोर्स के माध्यम से सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं डीडीए डायमंड ध्रूव तोमर (एयर-96) व डीडीए द्वारा संचालित फॉउंडेशन कोर्स प्रथम पग के छात्र दीपक देव (एयर-106) हैं। सभी सफल होने वाले छात्रों ने इसका पूरा श्रेय डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता व उपनिदेशक दिव्या गुप्ता के उचित मार्ग दर्शन के साथ फेकल्टी स्टाफ व स्टडी मटेरियल को दिया। साथ ही उन्होंने डीडीए द्वारा प्रत्येक सप्ताह कराये जाने वाले टेस्ट के साथ एग्जाम से पहले कराये जाने वाले ऑनलाइन व ऑफलाइन मॉक टेस्ट को भी बहुत उपयोगी बताया।

पीएम सूर्यघर योजना के लिए यूपीसीएल को मिला पुरस्कार

पीएम सूर्यघर योजना में लगातार चौथे साल उल्लेखनीय प्रदर्शन पर यूपीसीएल को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है। मंगलवार को जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि शामिल है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 14 हजार से अधिक घरों के ऊपर सोलर रूफ टॉप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कि करीब 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस मौके पर सचिव ऊर्जा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव रंजना राजगुरू भी उपस्थित थे।

'पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है, यह योजना परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करते हुए लोगों की आर्थिक की भी संवारने का एक माध्यम है. यूपीसीएल इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई का हकदार है

-पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री

डॉ. नरेश बंसल हुए गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान के सदस्य नामित

गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान (जीबीपीएन आईएचईएसडी) भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा नगर में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान सामाजिक, पारिस्थितिक, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच के जटिल संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जिससे भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) में स्थिरता बनाई रखी जा सके। संस्थान के मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित हैं, और इसके अतिरिक्त इसकी पांच अन्य इकाईयां गढ़वाल (श्रीनगर), हिमाचल (कुल्लू), सिक्किम (गंगटोक), पूर्वोत्तर (ईटानगर) तथा पर्वतीय प्रभाग (नई दिल्ली) हैं। डा. नरेश बंसल ने इसपर केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।

फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को राज्य में फिल्म विकास की गतिविधियों से अवगत कराया

डॉ. उपाध्याय ने पुलिस महानिदेशक श्री सेठ को नई फिल्म नीति 2024 की जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने में पुलिस विभाग की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिल्म शूटिंग अनुमति के लिये प्रत्येक जनपद में पुलिस विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है, जिससे अनुमति प्रक्रिया में सुगमता आ रही है। देश-विदेश के फिल्म निर्माता उत्तराखण्ड के शांत वातावरण एवं अच्छी कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर फिल्मों के निर्माण के लिये यहां आते हैं।

श्री दीपम सेठ ने उत्तराखण्ड फिल्म नीति की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग द्वारा फिल्म निर्माताओं को सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिये हर संभव सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों, जनपदीय नोडल अधिकारियों एवं फिल्म विकास परिषद की एक संयुक्त बैठक कर शूटिंग अनुमति प्रक्रिया में पुलिस विभाग से जुड़े सभी पक्षों पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया जायेगा। श्री सेठ ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस राज्य को एक आदर्श फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाने के लिये हर प्रकार से सहयोग करेगी।

इस अवसर पर डॉ. उपाध्याय द्वारा पुलिस महानिदेशक को उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद का स्मृति चिन्ह एवं नई फिल्म नीति की पुस्तिका भेंट की गई।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

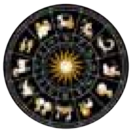
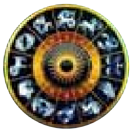
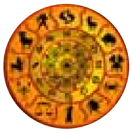

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– पुरानी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे। पूरे जोश और ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। अपने संपर्क सूत्रों का सही इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरों की मुश्किलें दूर करने में मदद मिलेगी। विपरीत परिस्थिति में विवाद करने से बचें। धैर्य और शांति रखें। मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने की स्थिति बन सकती है।

वृषभ राशि– दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। आपसी विचारों का आदान-प्रदान कई समस्याओं को सुलझाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को करियर से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। खर्चा करते समय बजट को नजरअंदाज न करें। दूसरों की मदद करने के साथ निजी कामों पर भी ध्यान दें, वरना इससे आपके काम अधूरे रह जाएंगे।

मिथुन राशि– हर काम करने से पहले विचार विमर्श करने से फायदा होगा। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को उपलब्धि मिल सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बीतेगा। आपको सुकून मिलेगा। बहुत अधिक सोच-विचार करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। उन पर काम करने पर ध्यान केंद्रित रखें।

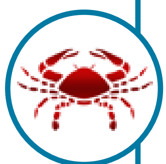

कर्क राशि– वरिष्ठ लोगों का सहयोग रहेगा। महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान दें। उन पर तुरंत काम शुरू करें। लक्ष्य प्राप्ति में निश्चित सफलता मिलेगी। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनेगी। पढ़ाई में भी मन लगेगा। नकारात्मक स्थिति बनने पर काल्पनिक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर तनाव हो सकता है।

सिंह राशि– आप विवेक और चतुराई से विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ समय बीताने का मौका मिलेगा। आपसी बातचीत से गिले शिकवे दूर होंगे। जोखिम भरे कार्यों में रुचि न लें। अपनी भावनाओं और आवेश पर संयम रखें। लापरवाही और आलस की वजह से महत्वपूर्ण कार्य टालना नुकसान का कारण बनेगा।

कन्या राशि– किसी योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। काफी समय से चल रही दुविधा दूर होने से सुकून मिलेगा। किसी विशेष काम को लेकर लोन लेने की कोशिश करें। तो आपकी समस्या हल हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा। मान-सम्मान बना रहेगा। कानूनी गतिविधियों से दूर रहने में भलाई है।

तुला राशि– नई उपलब्धियां इंतजार कर रही हैं। बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। सामाजिक स्तर पर आपको अनुभवी की मदद से पहचान मिलने वाली है। विरोधी आपके व्यक्तित्व के सामने हथियार डाल देंगे। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं को समय खराब नहीं करना चाहिए। लॉटरी, जुआ-सट्टा के कामों में नुकसान होने की आशंका है।

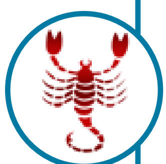

वृश्चिक राशि– अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ सुखद अनुभव हो सकते हैं। धार्मिक आयोजन में जाकर सुकून और शांति महसूस करेंगे। युवाओं की सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। अत्यधिक जिम्मेदारियां और काम से थक सकते हैं। तनाव में आकर कोई ऐसा फैसला न लें, कि बाद में पछताना पड़े। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम रखें।

धनु राशि– अपने काम पर भरोसा रखें। धैर्य से सभी काम मनचाहे तरीके से पूरे हो सकते हैं। घर में मौजमस्ती भरा वातावरण रहेगा। घर की सुख-सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी संभव है। घर-परिवार से संबंधित विपरीत परिस्थितियों का आपसी तालमेल से समाधान निकालने की जरूरत है। धैर्य और शांति रखें। मेहनत अधिक और फायदा कम होने जैसी स्थिति रहेगी।

मकर राशि– ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। हर काम समय पर करें। इससे आप अन्य गतिविधियों की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे। खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर की सुख-सुविधाओं संबंधी कामों में आपका का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मानसिक सुख-शांति रखने के लिए थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक गतिविधि में जरूर बीताएं।

कुंभ राशि– किसी दोस्त की मदद से आपकी समस्या हल होगी। घर और बाहर दोनों जगह सम्मानजनक स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों को मन पढ़ाई में लगेगा। व्यस्तता के बावजूद आप अपने निजी कामों के लिए समय निकाल लेंगे। साथ ही व्यावहारिक रहना भी जरूरी है। बहुत अधिक आदर्शवाद आपके के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

मीन राशि– तरक्की की खबर मिल सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे। उसका परिणाम भी उचित मिलेगा। गलत बात का विरोध करने से लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। आपको हर काम बड़ी संजीदगी और गंभीरता से करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027